

राजपत्र HRA का राजपश् The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मा			
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, M			0.0
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	क्रम सं	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
(कार्मिक और प्रक्रिक्षण विभाग)	1.	1230	6-10-79
अधिसूचना	2.	1418	1-12-79
नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009	3.	357	8-3-80
सा.का.नि. 228(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318	4.	977	. 27-9-80
के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के	5.	832	12-8-81
लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—	6	388	21-5-83
 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 2009 है। 	7.	640	3-9-83
	8.	584	30-5-84
़ (2) ये । जनवरी, 2006 को लागू समझे जाएंगे ।	9.	692	6-9-86
2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 के विनियम	10.	344	30-4-88
4 में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—	11.	583	30-7-89
"परंतु यह और कि 1 जनवरी, 2006 को और इसके पश्चात्	12.	379	4-6-90
आरंभ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली	13.	667(अ)	4-7-92
अवधि के लिए, अध्यक्ष नब्बे हजार रुपए प्रति मास का वेतन	14.	496(अ)	30-6-93
प्राप्त करेगा और प्रत्येक अन्य सदस्य अस्सी हजार रुपए प्रवि मास का वेतन प्राप्त करेंगे ।"	15.	373	2-7-93
[फा. सं. 39019/7/2008-स्था. (बी)]	16.	150(अ)	26-3-96
सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव	17.	719(अ)	3-12-97
पाद टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3,	18.	221	17-7-99
उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1402, तारीख 11	19.	230	28-4-01
अक्तूबर, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :	20.	450(अ)	28-6-07

स्पष्टीकारक ज्ञापन

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2006 से केंद्रीय सरकारी सेवकों के वेतनमान को पुनरीक्षित करते हुए अधिसूचना जारी की है। तथापि, उपरोक्त विनिश्चय उन संवैधानिक प्राधिकारियों को लागू नहीं है जिनके लिए पृथक उपबंध किए जाने की अपेक्षा है। अत:, केंद्रीय सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा समतुल्य श्रेणी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सिफारिश वेतमान की वृद्धि मंजूर की जाए। यह भी विनिश्चय किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन का पुनरीक्षण 1 जनवरी, 2006 से किया जाए, जैसा केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के निमित्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commsission (Members) Regulations, 1969, namely:—

- (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations, 2009.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.
- 2. In the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, in regulation 4, after the proviso, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided further that for the period beginning on and after the 1st January, 2006 and ending at the 30th April, 2007, the Chairman shall receive a pay of ninety thousand rupees per mensem and each of the other Members shall receive a pay of eighty thousand rupees per mensem".

[F. No. 39019/7/2008-Estt. (B)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification Number G.S.R. 1402 dated the 11th October, 1969 and subsequently amended by:—

Sl. No.	G. S. R. Number	Date of Publication	
1.	1230	6-10-79	
2.	1418	1-12-79	
3.	357	8-3-80 •	
4.	977	27-9-80	
5. .	832	12-8-81	
6.	388	21-5-83	
· 7.	640	3-9-83	
8.	584	30-5-84	
9.	692	6-9-86	
10.	344	30-4-88	
11.	583	30-7-89	
12.	379	4-6-90	
13.	667(E)	4-7-92	
14.	496(E)	30-6-93	
15.	373	2-7-93	
16.	150(E)	26-3-96	
17.	719(E)	3-12-97	
18.	221	17-7-99	
19.	230	28-4-01	
20.	450(E)	28-6-07	

Explanatory Memorandum

Based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the Government of India have since issued a notification revising the scale of pay of the Central Government Servants with effect from the 1st January, 2006. The above decision is, however, not applicable to constitutional authorities for whom separate provisions are required to be made. The Central Government has, therefore, decided that the Chairman and other Members of the Union Public Service Commission may also be allowed the increase in the scales of pay recommended by the Sixth Central Pay Commission for Central Government officers of equivalent grade. It has also been decided that the revision of pay of Chairman and other Members of the Union Public Service Commission be given effect from the 1st day of January, 2006 as has been done in respect of Central Government officers. It is certified that no person's interest shall be adversely affected by giving retrospective effect to these regulations.